शलभ श्रीराम सिंह की कविता

जमाने को बदलना है

जमाने को बदलना है
मजूर आ! किसान आ!
वतन के नवजवान आ!
तुझे सितम की सरहदों के पार अब निकलना है!
ये राह पुरखतर है पर इसी पे तुझको चलना है!
जमाने को बदलना है!
जमाने को बदलना है!
यहां पे मुद्दतों से आदमी ने है अश्क पिया
रहम करेंगे लोग इस उम्मीद पर बहुत जिया
मगर सवाल पेट का बिना जवाब के रहा
किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं कहा
तो उसने सर उठा लिया
नया बिगुल बजा दिया
उसी बिगुल की धुन में तेरे सुर को आज ढलना है!
ये राह पुरखतर है पर इसी पे तुझको चलना है!
जमाने को बदलना है!
जमाने को बदलना है!
ये आदमी की शक्ल में भटकते लोग कौन है?
कदम–कदम से खौफ से अटकते लोग कौन हैं?
न जिनके बाग में उम्मीद की कोई कली खिली!
अंधेरा पी के मर गए मगर न रोशनी मिली!
उन्हीं का ख़्वाह तू भी है
पसीना और लहू भी है
उन्हीं की यादगार का चिराग बन के जलना है!
ये राह पुरखतर है पर इसी पे तुझको चलना है!
जमाने को बदलना है!
जमाने को बदलना है!
ये जिनकी सांस–सांस में तड़प रही हैं बिजलियां
उन्हीं को मिल रही हैं रोज लाख–लाख धमकियां
ये डर है उनके लब पे भूख का सवाल आए ना
कि उनकी धमनियों में खून का उबाल आए ना
कहीं जबां न खोल दें
ये सच कहीं न बोल दें
हुकुमतों की खैर–ख्वाहियत को यों ही पलना है!
ये राह पुरखतर है पर इसी पे तुझको चलना है!
जमाने को बदलना है!
जमाने को बदलना है!
सुबह की रोशनी से जिसने इनको काट रखा है
दिलों की वादियों को साजिशों से बांट रखा है
सड़क पे खींच ला कि अब उसे सबक सिखा दे तू
वतन परस्त! इंकलाब करके अब दिखा दे तू
ये सच है इस 'जनून' से
शहीद! तेरे खून से
समन्दरे–निजाम को उबलना है! उबलना है!
ये राह पुरखतर है पर इसी पे तुझको चलना है!
जमाने को बदलना है!
जमाने को बदलना है!
जमीं के पूत से जमीन छिन ली गई यहां
जला उसी का घर, पड़ी उसी के पांव बेड़ियां
हुकूक मिल सके नहीं कभी अमन के रास्ते
कभी नहीं रही जमीन कायरों के वास्ते
'लहू–लहू' के राग में
जवां दिलों की आग में
हर इक चटाने–जुल्म को
पिघलना है! पिघलना है!
ये राह पुरखतर है पर इसी पे तुझको चलना है!
जमाने को बदलना है!
जमाने को बदलना है!
बहे अगर खिलाफ़ तो हवा का रुख बदल दे तू
जो सांप फन उठाते हैं तो उनका फन कुचल दे तू
जो हाथ तेरे हाथ से जुदा हैं उनको काट दे
जरूरतन जमीं को सरों से दोस्त पाट दे
तुझी को यह भी करना है!
कि खुद ब खुद उबरना है!
बहुत गिरा है तू कि अब सम्हलना है! सम्हलना है!
ये राह पुरखतर है पर इसी पे तुझको चलना है!
जमाने को बदलना है!
जमाने को बदलना है!

पेज 1 का शेष

'आप' से बाहर दिल्ली पुलिस; आपे से बाहर केजरीवाल

कहते हैं दिल्ली में पुलिस कमिश्नर (सीपी)हाथी पर बैठ कर आते हैं और गधे पर बैठ कर जाते हैं। ऐसा इस लिये कि जाते-जाते वे अपने मातहतों और जनता की नज़र में बेहद गिर चुके होते हैं, जबकि आने के समय बड़े-बड़े दावे करने का रिवाज सा है। कोई-कोई ही सयाना होगा जो काज़ल की इस कोठरी से बेदाग जा पाया हो। वर्तमान सी पी भीमसेन बस्सी की छवि एक ईमानदार एवं कर्मठ अधिकारी की रही है। गत वर्ष पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस को पेशेवर रूप से कार्यकुशल बनाने में कई पहल भी की हैं। नये सिरे से सभी को प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है। पर ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार का दबदबा जस का तस देखा जा सकता हे।

बस्सी से पहले सी पी ब्रजेश कुमार गुप्ता के कार्यकाल के दौरान थानों और चौकियों की बोली लगा करती थी। करीबन 2 वर्ष पहले बनी फ़िल्म 'जॉली एल एल बी' में कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिलता है। गुप्ता का हाल यह था कि अपराध नियन्त्रण का काम आंकड़ों की हेरा-फ़ेरी से पूरा किया जाता था। इस हेरा-फेरी के लिये मौखिक आदेश दिये जाते थे कि किस मद में कितने अपराधों को दर्ज किया जाय। यानी, अपराध हों चाहे जितने, दर्ज तो गुप्ता के निर्देशानुसार ही हो सकते थे। गुप्ता के बाद आये नीरज कुमार, जिनके कार्यकाल में दिसम्बर 2012 में दिल्ली बस बलात्कार कांड ने समूची कानून-व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। नीरज कुमार के जमाने में भी कमो-बेश गुप्ता वाला खेल ही चलता रहा।

गुप्ता और नीरज कुमार आंकड़ों के साथ जो हेरा-फ़ेरी कर रहे थे, वह बस्सी के आते ही उजागर हो गई। बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छीना-झपटी जैसे समाज को उद्वेलित करने वाले मामलों के दर्ज होने में 300 से 600 प्रतिशत तक कि वृद्धि हो गई। जाहिर है बस्सी से पहले इन मामलों को नज़रअंदाज़ करने की प्रथा चल रही थी। यह केजरीवाल की अनुभवहीनता ही कही जायेगी कि वे पहले चले आ रहे पाखंड को नहीं समझ सके। गणतन्त्र दिवस के भाषण में उन्होंने ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने पर ही निशाना साधे रखा जबकि जरूरत थी मुकदमे दर्ज न करके अपराध को छिपाने वालों की खबर लेने की।

दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार को जानने व रोकने में यदि केजरीवाल सरकार वास्तव में अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती है तो उसे दिल्ली पुलिस के पिछले 10 वर्ष के एस एच ओ से लेकर सी पी तक के अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच विजिलेंस अपने विभाग से करानी चाहिये। चाहे दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के आधीन न भी हो, विजिलेंस विभाग तो उनका ही अपना विभाग है। इस विभाग को भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमे दर्ज करने, गिरफ़्तारी व चालान की वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो पुलिस को होती हैं।

दुनिया में कहीं भी भ्रष्टाचार महज़ भ्रष्टाचारियों को पकड़ने से बन्द नहीं होता। इसके लिये उन सरकारी प्रणालियों व नीतियों को दुरूस्त करना पड़ता है जो भ्रष्टाचार की जनक हैं। लिहाज़ा दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार भी उसे लोकतान्त्रिक एवं पारदर्शी बनाये बिना नहीं जायेगा। इस दिशा में केजरीवाल की 'आप' पार्टी की कोई दिलचस्पी सामने नहीं आ रही है। केजरीवाल के इस मुद्दे पर महज आपे से बाहर होते रहने से लोग़ों की तालियां तो मिल सकती हैं पर लोग़ों को राहत नहीं मिल पायेगी।

लोकतंत्र का शासन

वे डंडों सहित तमाम बलवा विरोधी साजो-सामान से लैस थे। यह सब कुछ शान्ति भंग रोकने के लिए था; धारा 144 भी। दूसरे दिन जब धर्नाकर्तायों के एक समूह द्वारा पुलिस का घेरा तोड़ने में जबरदस्ती की गयी, पुलिस ने उनपर सीमित बलप्रयोग भी किया और बाद में मुकदमे भी दर्ज किये।

एक लोकतंत्र में लोगों के विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार से इतना सामंजस्य बिठाना जरूरी होगा। वैसे भी धरने में राज्य सरकार के शामिल होने से प्रथम दृष्टि में शान्ति भंग की आशंका अपने आप समाप्त हो गयी थी। वह अराजकता की आशंका का नहीं, ट्रैफिक संचालन का मसला रह गया जिसे दिल्ली पुलिस ने बखूबी निभाया। सरकारों द्वारा अराजकता के उदाहरण देखने हों तो 1984 का सिख संहार, 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस और 2002 का गुजरात संहार सटीक उदाहरण हैं। इनमें क्रमशः उत्तर प्रदेश की भाजपाई कल्याण सिंह सरकार, केंद्र की कांग्रेसी राजीव गांधी सरकार और गुजरात की भाजपाई नरेंद्र मोदी सरकार ने वास्तविक अर्थों में अराजक भूमिका निभायी। और मुंबई में राज ठाकरे तो लगातार निभा ही रहा है।

पेज 8 का शेष

चिकित्सा मुनाफ़ाखोरी में 'पार्क' भी उतरा

अपने उद्घाटन भाषणों में गवर्नर से लेकर राव नरेन्द्र व ऑस्कर फ़र्नाडिस आदि सभी ने शहर की आम जनता को इस अस्पताल से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवायें मिलने का भरोसा दिलाया तथा अस्पताल मालिकों से कहा कि वे गरीबों का भी ध्यान रखें। यहां सवाल यह पैदा होता है कि जो सरकार गरीबों से टैक्सों के रूप में मोटा धन वसूल कर भी उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्वों का निर्वाह नहीं करती तो उस व्यापारी को ही क्या पड़ी है जो अपने पल्ले से धन खर्च करके बिना मोटा मुनाफ़ा कमाये जनता की सेवा करे? एक के बाद एक अस्पताल तो तभी बनेंगे न जब वह मोटा मुनाफ़ा कमायेगा।

भाषण देने आये इन शासकों को पार्क जैसे व्यवसायिक अस्पताल में आकर भाषण झाड़ने का तो समय मिल गया लेकिन इसी शहर में उनके अपने (सरकारी) अस्पतालों की दुर्दशा देखने का बिल्कुल समय नहीं है। इस संवाद दाता ने जब ऑस्कर फ़र्नांडिस से ई एस आई अस्पतालों की दुर्दशा बयान करते हुए एक नज़र जरा उन पर भी मारने को कहा तो पूरी बेशर्मी के साथ स्थानीय विधायक एवं राज्य के श्रम मन्त्री शिवचरण लाल बोल उठे, ''अभी दो माह हुए हैं उस (एन एच 3 वाले) अस्पताल का अधिग्रहण हुए...। सब ठीक हो जायेगा धीरे-धीरे।''

ऑस्कर के नोटिस में जब यह लाया गया कि 300 बिस्तरों वाले (उनके आधीन) ई एस आई सी अस्पताल में मात्र 17 डॉक्टर 16 नर्सें हैं, शेष स्टाफ़ भी न के बराबर है तो उन्होंने कहा कि अच्छा वे उस अस्पताल को भी देख आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इस अस्पतासल की दुर्दशा का पहले से ज्ञान नहीं था। उन्हें एक-एक चीज का पता ही नहीं बल्कि सब कुछ हो ही उनके इशारे पर रहा है। लिहाजा, शर्मा-शर्मी वे उस अस्पताल में चले तो गये लेकिन यह कहते हुए कि उनके पास केवल 13 मिनट हैं। इन 13 मिनटों में वे निर्माणाधीन अस्पताल व मेडिकल कॉलेज की इमारत में घूम-फ़िर कर निकल गये। उन्हें वहां गत 45 वर्षों से चल रहे 300 बिस्तर वाले अस्पताल व उसमे आने वाले मरीज़ों की दुर्दशा को तो देखने तक की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। हो भी कैसे सकती है जब उन्हें असली चिन्ता चिकित्सा व्यापारियों की हो तो। सुधी पाठक कई बार पढ चुके हैं कि ई एस आई सी अस्पतालों को चलाने के नाम पर 15000/-तक मासिक वेतन पाने वाले मज़दूरों से उनके वेतन का 6.5 प्रतिशत वसूला जाता है। अकेले इस ज़िले में 5 लाख से अधिक ऐसे मज़दूरों से प्रतिवर्ष 209 करोड़ रुपये ई एस आई निगम द्वारा वसूलने के बावजूद मज़दूरों को इलाज के लिये नीम हकीमों अथवा निजी डॉक्टरों के पास भटकना पड़ता है।

चोर मचाये शोर: ऊंट बैठेगा किस ओर

जब सिक्का चल गया तो अमित ने पुलिस वालों से मोटे ब्याज (4 रुपये सैकड़ा) पर पैसा उधार लेने का सिलसिला शुरू किया। रिश्वतखोर पुलिसवालों की मुसीबत यह होती है कि काली कमाई को रखें कहां? ऐसे में अमित उन्हें काफ़ी मुफ़ीद नज़र आया। यद्यपि ऐसे पुलिस वालों की संख्या तो 50 से ऊपर बताई जाती है लेकिन 34 नामों की सूची तो 'मज़दूर मोर्चा' को पक्की मिल गयी है। इनमें से कुछ के तो 50 लाख से भी ऊपर के हैं। बाकी दस-बीस लाख के तो काफ़ी हैं। कुछ ग़रीब पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो लालचवश फंस गये। इन्होंने अपने गांव से अथवा रिश्तेदारी से 2 रुपये सैकड़े पर पैसा उठा कर अमित को दे दिया कि बैठेबिठाये दो रुप्या सैंकड़े का मुनाफ़ा खाते रहेंगे। अमित द्वारा इस प्रकार उधार ली गयी कुल रकम करीब 16 करोड़ होती है।

अमित ने कुछ दिन तो ब्याज दिया, लेकिन एक दिन अचानक हाथ खड़े कर दिये। गुंडे-बदमाशों व अपराध से डील करने वाले पुलिसकर्मियों ने अपनी रकम डूबती देखकर जब उसे हड़काया तो इसने एक सुसाइड नोट तैयार करके उसमें उन सब धमकी देने वालों के नाम लिख दिये तथा सुसाइड करने की धमकी देने लगा। बस फ़िर क्या था, दीवान को हड़काने वाले पुलिसिये खुद ही हड़क गये; बल्कि अपनी जान छुड़ाने के लिये कुछ न कुछ और देकर ही गये। आलम यह है कि आज एकभी पुलिसकर्मी यह कहने को तैयार नहीं कि उसने अमित से एक भी रुपया लेना है।

उक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी तफ़्तीश एन आई टी के ए सी पी रामचन्द्र राठी को सौंपी गयी है। सांगवान ने बताया कि ए सी पी राठी बार-बार उन्हें बुला कर मुकदमा वापस लेने का दबाव डाल रहा है। राठी, अमित व उसकी पत्नी को सामने बिठाकर बार-बार यही कहता है कि यह मुकदमा झूठा दर्ज कराया गया है, तुम्हारे पास डेढ करोड़ कहां से आये? राठी यह भी कहता है कि जिस (जेलर) के रुपये हैं उसे क्यों नहीं सामने आने देते? यानी राठी व अमित दोनों की एक ही भाषा है।

यदि मुकदमा वास्तव में ही झूठा है तो ए सी पी राठी को शिकायतकर्ता से आगे पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिये थी। उसमें दम और दिमाग़ है तो अपनी कलम से अखराज रिपोर्ट लिख कर दिखाये और जेलर अनिल कुमार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे।

अवैध निर्माण: नगर निगम अधिकारियों की लूट का बड़ा स्रोत

फ़रीदाबाद (मनीष) नगर निगम कमिश्नर चाहे कितने दावे करे कि उन्होंने अवैध निर्माणों पर अंकुश लगा दिया है मगर उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह शहर का दौरा करने पर पता चलता है। अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियों ने एन. आई. टी. पांच का ऐसा रूप बिगाड़ा है जिसे देखकर हर कोई दंग है।

वहीं दूसरी ओर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों व भूमाफियों की मिलीभगत से दिन दहाड़े सरकारी ज़मीनों को भी भूमाफियों द्वारा कब्जाया जा रहा है। जिसके चलते एक भूमाफिया ने तो पूरी की पूरी सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से फ्लैट बना दिए हैं और अपना ऑफिस भी 5 के ब्लॉक में सरकारी ज़मीन पर खोल दिया है। पिछले दिनों एन.एच.पांच के एच. ब्लॉक में इसी भूमाफिया की एक बिल्डिंग को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सील भी किया गया था लेकिन उसके बावजूद नोटों के दम पर बिल्डिंग धड़ल्ले से बनकर तैयार हुई और बिककर आबाद हुई।

इसी तरह एन.एच. पांच में पिछले दिनों पांच जे. 34 में अवैध रूप से चौथी मंजिल का निर्माण कार्य जोरों पर था इसके एवज में नगर निगम अधिकारियों ने इस बिल्डर से मोटी रकम मांगी। लेकिन इस बिल्डर ने मोटी रकम देने से इंकार कर दिया। तभी नगर निगम अधिकारियों ने ड्रामेबाज़ी कर बिना सरकारी कागज़ों में दिखाए इस बिल्डिंग को सील कर दिया। बिल्डर ने इसका विरोध किया तो निगम अधिकारियों ने थाना प्रभारी एन आई टी अनिल कुमार को लिखित शिकायत देकर बिल्डर पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया।

मजेदार बात यह है कि जिस तेजी से निगम अधिकारियों ने पांच जे-34 व 5 एच-48 पर ड्रामेबाज़ी कर नकली सील लगाई थी वहीं इन्हीं बिल्डरों से लाखों रुपए की मोटी रकम लेकर इन सीलों को खुलवा दिया और यह सरकारी लूट चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम हुई है। जाहिर है यह लूट कोई छोटा-मोटा अधिकारी अकेले तो कर नहीं सकता। इसके लिये उच्चाधिकारियों व राजनेताओं का आशीर्वाद एवं संरक्षण होना जरूरी है।